BA Part II
IV^th Paper

सार्वजनिक ऋण और आर्थिक विकास :-
(Public debts & economic development)

18/7/20

आर्थिक विकास एक बहुआयामी और जटिल प्रक्रिया है। इसमें एक सुसंगठित लोक ऋण नीति का महत्त्वपूर्ण योगदान हो सकता है; परंतु ऐसी ऋण नीति की संरचना और उसके कार्यान्वयन में अनेकों कठिनाइयाँ आती हैं।

1. वित्तीय ढाँचे का विकास (Development of financial System) :- आर्थिक विकास के साथ मुद्रा और साख की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है, जिसके दो कारण हैं—
आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी तथा उनमें मुद्राकृत मुद्राकृत गतिविधियों के अनुपात में दीर्घकालीन वृद्धि होती है।
अर्थव्यवस्था में वित्तीय लेन-देन के सभी करार (agreements) करेंसी की मात्राओं में होने के कारण सरकार की वित्तीय देयताओं में वृद्धि किए बिना उपरोक्त बढ़ती आवश्यकता की पूर्ति नहीं की जा सकती। करेंसी समस्त वित्तीय ढाँचे की बुनियाद का काम देती है; तथा सामान्यतः करेंसी की प्रचलित मात्रा बढ़ाने के लिए सरकार को उधार लेना पड़ता है (विशेषकर केन्द्रीय बैंक से) यह भी स्मरणीय है कि यदि सरकार उधार लेने में लापरवाही बरते, अथवा ऋण राशियों को उपभोग व्यय-मदों पर लगा दे, तो अर्थव्यवस्था का वित्तीय ढाँचा लाभान्वित होने के स्थान पर क्षतिग्रस्त हो सकता है।

2. बचत एवं पूँजी-निर्माण (Saving and capital formation) - प्रत्येक अर्थव्यवस्था को अपनी उत्पादन क्षमता बनाए रखने के लिए बचत और निवेश की आवश्यकता होती है। एक अल्पविकसित देश की यह आवश्यकता और भी अधिक होती है। परंतु ऐसी अर्थव्यवस्था को बचत और पूँजी निर्माण में सामान्य से अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रतिव्यक्ति आय के कम होने के कारण तथा गरीब लोगों की संख्या अधिक होने के कारण इसकी बचत क्षमता अति कम होती है। इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार से कुछ प्रभावी कदमों की अपेक्षा की जाती है। सरकार यदि अपनी राजस्व प्राप्तियों में से समुचित बचत और पूँजी निवेश करने में असमर्थ हो तो उधार लेकर उन मदों पर व्यय कर सकती है जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से बचत, निवेश तथा अर्थव्यवस्था की

Scanned by CamScanner

उत्पादन क्षमता में वृद्धि करते हों।
परंतु कुछ परिस्थितियों में सरकार द्वारा उधार लेकर पूँजी निवेश बढ़ाने की नीति के परिणाम संदिग्ध भी हो सकते हैं। उदाहरणार्थ इसके द्वारा पूँजी-निर्माण के लिए बाज़ार से उधार लेने पर निवेश संसाधन निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में हस्तांतरित हो जाते हैं। और इसके साथ यदि निजी क्षेत्र क्षेत्र में निवेश की दर घट जाए तो देश की संयुक्त निवल निवेश दर का बढ़ना अनिश्चित हो जाता है। इसी प्रकार का अनिश्चित परिणाम सरकार द्वारा केन्द्रीय बैंक से उधार लेने का भी हो सकता है। पश्चायुक्त स्थिति में प्रचलित करेंसी की मात्रा के साथ साथ कीमतें बढ़ जाती हैं जिनसे निजी क्षेत्र के स्वामित्व वाले वित्तीय संसाधनों की क्रय-शक्ति घट जाती है और इससे बचत और निवेश घट सकते हैं।

सार्वजनिक ऋण अर्थव्यवस्था के निवेश संसाधनों का विकासोन्मुख पुनर्गठन भी आर्थिक विकास में सहायक हो सकता है। आशा यह की जाती है कि सरकार वाणिज्यिक लाभ को प्राथमिकता न देते हुए अपने निवेश-निर्णय इस प्रकार लेगी जिससे देश की दीर्घकालीन उत्पादन-क्षमता में समुचित वृद्धि हो। उदाहरणार्थ सरकार अवसंरचनात्मक सुविधाओं (infrastructural facilities) के विकास हेतु निवेश करेगी, क्योंकि वाणिज्यिक दृष्टि से लाभकारी न होते हुए भी इनसे अर्थव्यवस्था में की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि होती है। इसके विपरीत निजी क्षेत्र से यही अपेक्षा की जा सकती है कि इसकी निवेश गतिविधियाँ वाणिज्यिक लाभ की संभाविता के अनुरूप होंगी, जिससे अर्थव्यवस्था के कई आधारभूत सुविधाओं के वंचित रह जाने का भय बना रहेगा।

ध्यानयोग्य है कि सरकार द्वारा सार्वजनिक उधार की प्राप्तियों को उपभोग व्यय एवं अन्य अनुत्पादक मदों पर लगा देने पर आर्थिक विकास के प्रोत्साहित होने की आशा नहीं की जा सकती। परंतु सार्वजनिक उधार से लोक कल्याण की योजनाओं के वित्त-पोषण की नीति विवादास्पद है। एक मतानुसार लोक-कल्याण के वित्त-पोषण के लिए सरकार को उधार लेकर नहीं, बल्कि कर तथा कर-भिन्न राजस्व में बढ़ोतरी तथा अपने अनावश्यक व्यय में कटौती द्वारा साधन जुटाने चाहिए।

मुद्रास्फीति (Inflation)- केन्द्रीय बैंक से उधार लेने सहित लोक ऋण में बढ़ोतरी की कुछ विधियों से मुद्रास्फीति और कीमतें बढ़ती हैं। इन प्रवृत्ति प्रवृत्तियों का देश के आर्थिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है, यद्यपि इस

Scanned by CamScanner

प्रभाव की रूपरेखा परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है।
मुद्रास्फीति अथवा कीमतों में वृद्धि तथा सार्वजनिक ऋण में एक गहरा संबंध है। परंतु एक ऋण लेती सरकार यह दर्शाने की चेष्टा करती है कि उसकी इस गतिविधि के कारण कीमतों में वृद्धि होने की कोई संभावना नहीं है। इस दावे की व्याख्या निम्न प्रकार से दी जाती है। जब सरकार निवेश-व्यय के लिए उधार लेती है, तो उसका यह कथन रहता है कि इससे समग्र मांग में निवल-वृद्धि नहीं होती, केवल निवेश व्यय निजी क्षेत्र के स्थान पर सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किया जाता है। सरकार यह दावा उस समय भी करती है जब वह सार्वजनिक ऋण द्वारा संग्रोजित साधनों को निवेश मदों में न लगाकर उन्हें अपने उपभोग के लिए व्यय कर रही हो। सरकार का यह तर्क रहता है कि इस दशा में भी समग्र मांग में कोई निवल वृद्धि नहीं होती, तथा इस कारण कीमतों पर भी कोई दबाव नहीं पड़ता।

उपर्युक्त तर्क के दोनों घटक भ्रामक हैं। तथ्य यह है कि बजटीय घाटे के कारण समग्र मांग में बढ़ोतरी के साथ-साथ संसाधनों के आवंटन में भी इस प्रकार का परिवर्तन आता है जिससे पूर्ति-प्रवाह स्थगित होते हैं। स्पष्ट है कि इन दोनों घटकों द्वारा कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति सक्षम होती है। हमारे इस कथन की व्याख्या निम्नलिखित है-

(क) सरकारी निवेश बहुधा उपभोग वस्तुओं के उत्पादन के लिए न होकर पूँजी-वस्तुओं के उद्योगों में तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं के मुहैया करने में जाता है। आर्थिक विकास में दीर्घकालीन बढ़ोतरी सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना अति-उचित तथा लाभकारी है। परंतु कीमतों में वृद्धि के दृष्टिकोण से यह नीति विवादास्पद है। इस प्रकार के निवेश व्यय से लोगों की मौद्रिक आय तथा मांग में तो उसी समय वृद्धि हो जाती है, परंतु इस मांग की तुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति बढ़ने में काफी समय लग जाता है। परिणामस्वरूप मांग और पूर्ति में इस प्रकार का असंतुलन आने के कारण कीमतों पर दबाव बढ़ता है।

(ख) जब सरकारी उधार केन्द्रीय बैंक से लिया गया हो, तो करेंसी की प्रचलित मात्रा उधार में निवल वृद्धि के बराबर बढ़ जाती है। यही स्थिति घाटे के बजट को "शेकड़ शेष" में निवल कमी (drawing down of cash balances) के द्वारा पूरा करने पर भी लागू होती है। करेंसी की प्रचलित मात्रा में वृद्धि से बैंकों की साख सृजन क्षमता में बढ़ोतरी होने के परिणामस्वरूप मांग और कीमत वृद्धि प्रोत्साहित होते हैं।

Scanned by CamScanner